sion of competent technical personnel, who will directly report to the Chief Executive.

26. A separate environmental management cell with suitable qualified people to carry out various functions should be set up under the control of a senior executive who will report directly to the head of the organisation.

27. The funds earmarked for the environmental protection measures should not be diverted for other purposes and year-wise expenditure should be reported to this Ministry.

28. The Ministry may revoke clearance if implementation of the conditions is not satisfactory.

29. These conditions will be enforced *inter alia* under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1991, an Environment (Protection) Act, 1986 along with their amendments.

Pollution of Rivtr Hooghly

*115. SHRI SOM PAL: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) Whether some studies have recently been conducted in the estuarine water of river Hooghly to ascertain the pollution levels; and

(b) if so, what are the findings thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) Yes, Sir. The National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur is conducting a study for the pollution level in the Kalyani to Birlapur stretch of the river Hooghly to update the available data in this regard. The report on the study is awaited.

Observance of Bharat Ekta Varsh

*116. SHRI BEKAL UTSAHI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision in respect of observing the year 1992 as the "Bharat Ekta Varsha"; and

(b) if so, the details thereof indicating the schemes to be carried out as a part of this observance?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Depiction of Forest area by the Paper Industry

*117. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that huge forest area is being depleted by the paper indusry in the country; and

(b) if so, what steps Government have taken to remedy the situation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) No, Sir.

The forest base paper milsl use mainly Eucalyptus and bamboo as their raw material. The entrie supply of eucalyptus wood comes from plantations. These eucalyptus plantations are easily regenerated by coppice growth after their harvest. Bamboo extraction however, is carried out mainly from natural forests and its extraction is strictly regulated by working plan prescriptions for that area. Bamboo working areas in the country are by and large covered by working plans.

(b) In order to relieve pressure on the country's forests for raw materials, the government are encouraging manufacture of paper from agricultural wastes. Presently, agricultural waste based mills are estimated to contribute about 30 percent of the total paper production in the

country. In addition, Farm Forestry and Agro-Fofestry are being promoted out side the forest areas.

बड़े बन्दरगाहों के कार्यों में गैर-सरकारी क्षेत्र को सम्मिलित किया जाना

*118. **डा. बापू कालदाते :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के बड़े बंदरगाहों के कार्यों में गैर-सरकारी क्षेत्र को सम्मिलित करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन बंदरगाहों पर अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपी जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) स्टीवडोरिंग क्लीअरिंग और माल भेजने जैसे कुछेक पत्तन कार्यों में निजी क्षेत्र को सहभागिता पहले से ही प्रचलित है । और कुछ पत्तनों में, कुछ कार्गो हैंडलिंग उपकरण निजी क्षेत्र द्वारा सप्लाई तथा प्रचालित किए जाते हैं ।

(ख) और (ग) पत्तनों से कहा गया है कि अतिरिक्त सुविधाएं बढ़ाने पर विचार करते समय भी निजी क्षेत्र की सहभागिता की संभावना की भी जांच की जाए । प्रत्येक मामले की उसके गुणावगुण के आधार पर जांच की जाएगी ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों द्वारा समय की पाबन्दी का पालन

*119. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में अधिकांश डाक्टर और अन्य कर्मचारी समय की पाबंदी नहीं बरतते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम.एल. फोतेदार) : (क) समय पाबंदी का आम तौर पर डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों दोनों द्वारा पालन किया जाता है । तथापि, ऐसे दृष्टांत हुए हैं जहां कर्मचारियों ने समय पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं किया है । ऐसा मुख्य रूप से उन कर्मचारियों के मामले में हुआ है जिन्हें सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करके लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है ।

(ख) औषधालयों में डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों के मामले में समय-पाबंदी का अनुवीक्षण करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) औषधालयों में उपस्थिति रजिस्टर का रख-रखाव करना जिनमें डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों का आने और जाने का समय नोट किया जाता है ।

(ii) समय-पाबंदी को सुनिश्चित करने हेतु जोनल अपर निदेशकों द्वारा नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण करना ।

(iii) डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों को समय-पाबंदी का अनुपालन करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी करना ।

Development of Ladakh

*120. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ladakh Buddhist Association has been demanding special attention to the developmental problems of Ladakh; and